



# INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND INTERDISCIPLINARY STUDIES

(Peer-reviewed, Refereed, Indexed & Open Access Journal)

DOI : 03.2021-11278686

ISSN : 2582-8568

IMPACT FACTOR : 8.031 (SJIF 2025)

“राजस्थान राज्य के वर्तमान ग्रामीण शैक्षिक परिदृश्य में ‘आदर्श विद्यालय योजना’ की भूमिका”  
(भीलवाड़ा ज़िले के आसीन्द एवं बदनोर ब्लॉक्स के विशेष सन्दर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन)

“Role of the ‘Adarsh Vidyalaya Yojana’ in the Present Rural Educational Scenario of Rajasthan State” (An Analytical Study With Special Reference to Asind & Badnor Blocks of Bhilwara District)

नारायण लाल बलाई

(शोधार्थी)

शिक्षा संकाय,

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय,

उदयपुर (राजस्थान, भारत)

डॉ. अख्तर बानो

(शोध मार्गदर्शक)

विद्या भवन गो.से. शिक्षक महाविद्यालय,

उदयपुर (राजस्थान, भारत)

DOI No. 03.2021-11278686

DOI Link :: <https://doi-ds.org/doi/10.2025-48489322/IRJHIS2502005>

## सारांश:

आदर्श विद्यालय योजना राजस्थान में ग्रामीण शिक्षा को सशक्त बनाने की एक महत्वपूर्ण पहल रही है, जिससे शैक्षिक सुधार, अवसंरचना विकास और प्रशासनिक संरचना में सकारात्मक बदलाव आए हैं। इस योजना के तहत कक्षा 11 और 12 में विद्यार्थियों के नामांकन में 57.41% की वृद्धि हुई, जिससे शिक्षा के प्रति जागरूकता और रुचि बढ़ी। साथ ही, ड्रॉपआउट दर में 79.67% की कमी आई, जिससे छात्रों को शिक्षा में बनाए रखने में मदद मिली। विद्यालयों में पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं और खेल सुविधाओं का विस्तार हुआ, जिससे समग्र शैक्षिक अनुभव बेहतर हुआ। स्मार्ट स्कूल प्रणाली, डिजिटल शिक्षा सामग्री और प्रशासनिक सुधारों ने शिक्षा की गुणवत्ता को और अधिक प्रभावी बनाया। इसके अलावा, राज्य सरकार की वित्तीय और नीतिगत सहायता इस योजना की सफलता में महत्वपूर्ण रही है। कुल मिलाकर, यह योजना ग्रामीण शिक्षा के स्तर को सुधारने में प्रभावी रही है, हालांकि कुछ क्षेत्रों में अभी भी सुधार की आवश्यकता बनी हुई है।

## 1. प्रस्तावना :

*"Education is not preparation for life; education is life itself."*

*John Dewey(1916)*

“शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं अपितु शिक्षा जीवन ही है”। जॉन ड्युई का कथन वास्तव में शिक्षा के वृहद् रूप को स्थापित करता है। शिक्षा के बिना जीवन निरर्थक है। शिक्षा ही जीवन की आधारशिला है। हम दैनिक जीवन में शिक्षा का भौतिक संसाधनों (धन, दौलत, जमीन) के तुली मानते हैं तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल होगी।

शिक्षा जीवन की वह मजबूत जड़ है (बुनियाद) है जिसका कोई विकल्प हो ही नहीं सकता है। शिक्षा से मनुष्य जीवन को अर्थ मिलता है। जीवन की गुणवत्ता, चरित्र, आचरण शिक्षा से ही स्थापित होता है। किसी भी समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए चाहे वह आर्थिक हो या सामाजिक हो या सांस्कृतिक परन्तु शैक्षणिक विकास ही सर्वप्रथम स्थान रखता है।

भारतीय संविधान, भारत की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करता है। संविधान की उद्देशिका हमारे सामाजिक दर्शन को रेखांकित करती है। संविधान में वर्णित श्रेष्ठ सिद्धांत ही हमारे शैक्षिक नियोजन, कार्यान्वयन एवं प्रबंधन को आकार प्रदान करते हैं। भगवद्गीता में ज्ञान को धरती पर सबसे पवित्र कहा गया है-

“न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते” अर्थात् ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है।

इसी विचारधारा के दृष्टिगत भारतीय संविधान में समस्त नागरिकों हेतु शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया है। शिक्षा से सम्बंधित संवैधानिक प्रावधान राष्ट्र के समुचित विकास एवं लोकतंत्र के सफलता हेतु प्रारंभिक शिक्षा के महत्व को इंगित करते हैं। जैसा कि सर्वविदित है प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था वह आधार है जिस पर किसी देश की सम्पूर्ण शिक्षा का ढांचा खड़ा होता है। एक देश तभी अपनी शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ कर सकता है जब वह अपनी प्रारम्भिक शिक्षा प्रणाली की कमियों तथा कमजोरियों को दूर कर पाए। चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है अतः केंद्र सरकार के साथ ही प्रत्येक राज्य अपनी सामाजिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप अपने नागरिकों हेतु शिक्षा की उत्तम सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के सबसे बड़े और विषम भौगोलिक विशेषताओं वाले राज्य राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व विभिन्न देसी रियासतों की अपनी शिक्षा व्यवस्था थी। किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति पश्चात् राज्य में सन् 1950 में शिक्षा विभाग के अंतर्गत बीकानेर में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना हुई। अपनी स्थापना के समय से ही निदेशालय केंद्र सरकार के निर्देशन एवं राज्य सरकार के नियंत्रण में शिक्षा के क्षेत्र में निरन्तर प्रयत्नशील है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार शिक्षा के सार्वजनीकरण, बालिका शिक्षा संवर्धन एवं शैक्षिक गुणवत्ता के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु राज्य के शिक्षा निदेशालय द्वारा समय समय पर प्रासंगिक योजनायें लागू की जाती रही हैं जिनके परिणामस्वरूप राजस्थान जैसे शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्य में भी आशानुरूप परिणाम परिलक्षित होने लगे हैं। राजस्थान में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अब तक चलाई जाने वाली मुख्य योजनाओं में ऑपरेशन ब्लेक बोर्ड योजना, शिक्षा कर्मी योजना, लोकजुम्बिश योजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, आदिवासी क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय योजना, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना, राजीव गांधी पाठशाला योजना, आपकी बेटी योजना, बालिका प्रोत्साहन योजना, गार्गी योजना, अनुप्रति योजना, उत्कृष्ट विद्यालय योजना, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल योजना, महात्मा गाँधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल एवं आदर्श विद्यालय योजना प्रमुख हैं।

राजस्थान की मुख्यमंत्री ने 2015-16 के बजट में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक विद्यालय को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने की घोषणा की। यह विद्यालय अन्य विद्यालयों के लिए मार्गदर्शक और संसाधन केंद्र बनेंगे। आगामी तीन वर्षों में इन्हें "Centre of Excellence" के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया।

अब तक कुल 9,895 ग्रामीण क्षेत्र के आदर्श विद्यालयों में से 5,590 तथा शहरी आदर्श के कुल 281 विद्यालयों में से 197 आदर्श विद्यालय विकसित हो चुके हैं। इस प्रकार कुल 5,787 आदर्श विद्यालयों को पूर्ण रूप से विकसित किया जा चुका है।

जब विशेष योजना को स्कूल के प्रबंधन और निर्णय-निर्माण में शामिल किया जाता है, तो यह विद्यालयों के समग्र विकास और छात्रों के प्रदर्शन में सुधार करता है। विशेष रूप से, ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष प्रोत्साहन से विद्यालयों की बुनियादी सुविधाओं, शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों के नामांकन दर पर प्रभाव पड़ता है। 'आदर्श विद्यालय योजना' से विद्यालयों में शैक्षिक संसाधन, मानव संसाधन, सामुदायिक भागीदारी, शिक्षक प्रशिक्षण, वित्तीय प्रबंधन इत्यादि में क्या बदलाव आया है यह जानने के लिए हमारे मस्तिष्क में निम्नांकित शोध प्रश्न उभरते हैं-

## 2. शोध प्रश्न (Research Questions):

- i. आदर्श विद्यालय योजना अपने लक्ष्यों (Goals) को प्राप्त करने में कहाँ तक सफल सिद्ध हुई है?
  - (ii). क्या आदर्श विद्यालय योजना का क्रियान्वयन (Implementation) समुचित रूप से हो पाया है?
  - (iii). क्या आदर्श विद्यालय योजना के क्रियान्वयन से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक परिदृश्य (Educational Scenario) में परिवर्तन हुआ है?
- iv. क्या आदर्श विद्यालय योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् विद्यालयों के सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrollment Ratio) में सार्थक वृद्धि हुई है?
- v. क्या आदर्श विद्यालय योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ देने की दर (Drop Out Rate) में कमी आई है अथवा नहीं?

## 3. समस्या कथन (Statement of the Problem) :

“राजस्थान राज्य के वर्तमान ग्रामीण शैक्षिक परिदृश्य में 'आदर्श विद्यालय योजना' की भूमिका“ (भीलवाड़ा ज़िले के आसीन्द एवं बदनोर ब्लॉक्स के विशेष सन्दर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन)

## 4. शोध के उद्देश्य :

यह अध्ययन निम्नलिखित उद्देश्यों से निर्देशित है -

- i. आदर्श विद्यालय योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrollment Ratio) में हुई वृद्धि का पता लगाना।
- ii. आदर्श विद्यालय योजना के क्रियान्वयन से विज्ञान, कला एवं वाणिज्य वर्ग के सकल नामांकन (Gross Enrollment to Science Faculty) में आए परिवर्तन का पता लगाना।
- iii. आदर्श विद्यालय योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ देने की दर (Drop Out Rate) के आंकड़ों का पता लगाना।
- iv. आदर्श विद्यालय योजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रारंभिक शिक्षा के शैक्षिक-प्रशासनिक ढांचे (Administrative Structure for Education) में हुए परिवर्तन का विश्लेषण करना।
- v. आदर्श विद्यालय योजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं (Infrastructure Facilities) एवं भौतिक संसाधनों (Physical Resources) में हुए परिवर्तनों का पता लगाना।

vi. आदर्श विद्यालय योजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक (Teaching And Non Teaching) श्रेणी के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों के आँकड़ों का पता लगाना।

#### 5. न्यादर्श (Sample):

इस शोधकार्य हेतु राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसीन्द एवं बदनोर ब्लॉक्स को निम्नांकित रूप से न्यादर्श में सम्मिलित किया गया है-

#### सारणी संख्या-1.1

#### न्यादर्श

क्र.सं.	अभिधारक	आसीन्द	बदनोर	कुल संख्या
1.	विद्यार्थी	45	45	90
2.	शिक्षक	18	18	36
3.	संस्था प्रधान	9	9	18
4.	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी	1	1	2
5	जिला शिक्षा अधिकारी	-	-	1
7.	योग	91	91	147

#### 6. न्यादर्श चयन की विधि:-

प्रस्तुत शोध में समस्या की प्रकृति के अनुसार यादृच्छिक प्रतिचयन विधि एवं सौद्देश्य प्रतिचयन विधि का प्रयोग किया गया।

#### 6.1 न्यादर्श का आकार:-

इस शोध में अध्ययन हेतु राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसीन्द एवं बदनोर ब्लॉक के 'आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयों' का चयन किया गया।

- विद्यालयों का चयन – सौद्देश्यपूर्ण विधि से चयन।
- विद्यार्थियों का चयन – 12वीं कक्षा के 90 विद्यार्थियों का लॉटरी विधि से चयन (प्रत्येक ब्लॉक से 9 विद्यालय, प्रत्येक विद्यालय से 5 विद्यार्थी)।
- शिक्षकों का चयन – 36 शिक्षकों का लॉटरी विधि से चयन।
- संस्था प्रधानों का चयन – सौद्देश्यपूर्ण विधि 18 प्रधानाध्यापकों का चयन।
- शिक्षा अधिकारियों का चयन – 2 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं 1 जिला शिक्षा अधिकारी का सौद्देश्य विधि से चयन।

#### 7. शोध का औचित्य (Significance of the Research Study):

इस शोध के माध्यम से राज्य सरकार यह जान सकेगी कि आदर्श विद्यालय योजना अपने उद्देश्यों को कितनी सफलतापूर्वक पूरा कर रही है और इसमें सुधार की क्या संभावनाएँ हैं। शिक्षा विभाग को इससे योजना की क्रियान्विति की उपयुक्तता और क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों की जानकारी मिलेगी, जिससे आवश्यक सुधार

किए जा सकेंगे। शैक्षिक नियोजकों, प्रशासकों एवं प्रबंधकों के लिए यह शोध योजना की उपलब्धियों और चुनौतियों की पहचान करने में सहायक होगा, जिससे इसे अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। भविष्य के अनुसंधान की दृष्टि से यह अध्ययन अन्य शोधकर्ताओं को प्रेरित करेगा कि वे इस क्षेत्र में आगे अनुसंधान करें और योजना को और अधिक प्रभावशाली बनाएं। विद्यार्थियों को इस शोध से आदर्श विद्यालय योजना के प्रभावों की जानकारी मिलेगी, जिससे वे अपने निकट स्थित श्रेष्ठ विद्यालयों का चयन कर सकेंगे। अभिभावकों को भी इससे आदर्श विद्यालयों में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी मिलेगी, जिससे वे अपने बच्चों के लिए उचित विद्यालय चुन सकेंगे और इसके विकास में योगदान दे सकेंगे।

#### 8. शोध समस्या का परिसीमन :

प्रस्तुत शोध का परिसीमन निम्न प्रकार से है-

यह शोध कार्य भीलवाड़ा जिले के आसीन्द एवं बदनोर ब्लॉक्स के ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित है। इसमें केवल आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों को शामिल किया गया है। अध्ययन के प्रमुख विषयों में विद्यार्थी नामांकन, ड्रॉपआउट दर, लक्षित जनसंख्या सर्वेक्षण, शिक्षकों की पदस्थापन स्थिति, भौतिक संसाधन, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, विद्यालय पर्यावरण और विभिन्न शैक्षिक गतिविधियाँ शामिल हैं।

#### 9. शोध विधि एवं प्राविधि :

शोध कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत शोध के अन्तर्गत वर्णात्मक एवं आदर्शमूलक विधि का प्रयोग किया गया है तथा व्याख्या एवं विश्लेषण हेतु प्रतिशत का उपयोग किया गया है।

#### 10. शोध उपकरण (Research Tools) :

प्रस्तुत शोध में निम्नांकित स्वनिर्मित उपकरणों का प्रयोग किया गया है-

इस अध्ययन हेतु कक्षा 12 के विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए प्रश्नावली तैयार की गई है, जिससे उनके विचारों और अनुभवों को संकलित किया जा सके। प्रधानाचार्यों (प्रशासकों), शिक्षा अधिकारियों (CBEO एवं DEO) और विद्यार्थियों के अभिभावकों के लिए अर्द्धसंचरित साक्षात्कार अनुसूची का उपयोग किया गया, ताकि गहराई से जानकारी प्राप्त की जा सके। वहीं, शोधार्थियों के लिए अवलोकन प्रपत्र निर्धारित किया गया है, जिससे वे अध्ययन की प्रक्रियाओं और निष्कर्षों का विश्लेषण कर सकें।

#### 11. दत्त विश्लेषण एवं व्याख्या:

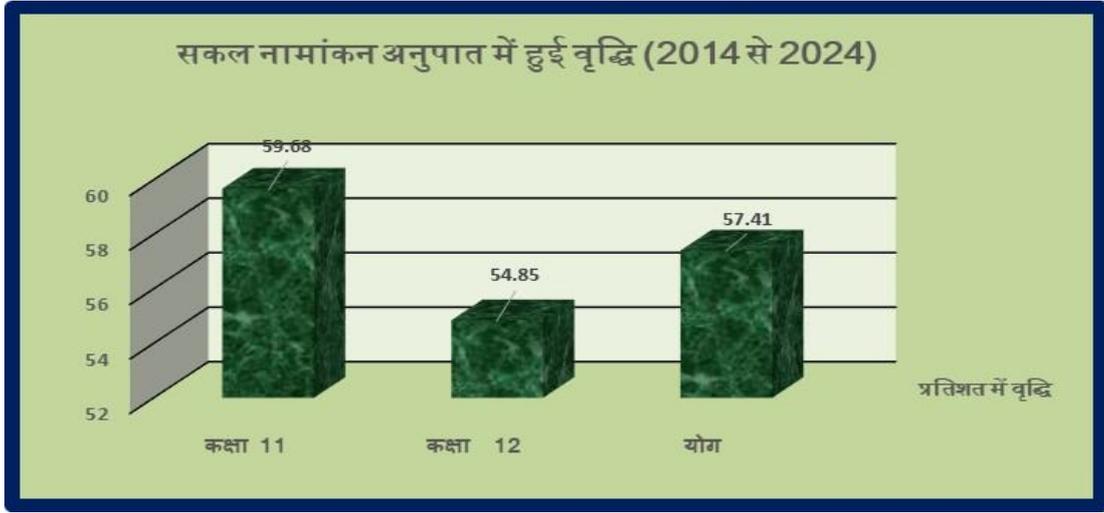
##### सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrollment Ratio)

##### 1. आदर्श विद्यालय योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् सकल नामांकन अनुपात:-

आदर्श विद्यालय योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् सकल नामांकन अनुपात में हुई वृद्धि।

सारणी संख्या:-1.2

कक्षा	2014	2024	प्रतिशत में वृद्धि
कक्षा 11	925	1477	59.68
कक्षा 12	815	1262	54.85
योग	1740	2739	57.41



आरेख संख्या:1.1

### विक्षेपण एवं व्याख्या:-

सारणी संख्या 1.2 एवं आरेख संख्या 1.1 से स्पष्ट है कि 2014 से 2024 के बीच कक्षा 11 और कक्षा 12 में छात्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

- कक्षा 11 में छात्रों की संख्या 925 से बढ़कर 1477 हो गई, जो 59.68% की वृद्धि दर्शाती है।
- कक्षा 12 में यह संख्या 815 से 1262 हो गई, जो 54.85% की वृद्धि को दर्शाती है।
- कुल मिलाकर, दोनों कक्षाओं में छात्रों की संख्या 1740 से 2739 हो गई, जो 57.41% की वृद्धि को दर्शाता है।

इस वृद्धि के पीछे कई संभावित कारण हो सकते हैं, जैसे कि शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता, सरकारी योजनाएँ, बेहतर शैक्षणिक सुविधाएँ, या स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार।

2. आदर्श विद्यालय योजना के क्रियान्वयन से विज्ञान, कला एवं वाणिज्य वर्ग के सकल नामांकन (Gross Enrollment to Science Faculty) में हुई वृद्धि

सारणी संख्या:-1.3

वर्ग	2014	2024	कुल वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि
विज्ञान (विद्यार्थी)	302	519	217	71.85
कला (विद्यार्थी)	359	649	290	80.78
वाणिज्य (विद्यार्थी)	191	278	87	45.60



आरेख संख्या 1.2

**विक्षेपण एवं व्याख्या:-**

सारणी संख्या 1.3 एवं आरेख संख्या 1.2 से स्पष्ट है कि 2014 से 2024 तक विज्ञान में 71.85% वृद्धि (217 विद्यार्थियों की वृद्धि), कला में 80.78% वृद्धि (290 विद्यार्थियों की वृद्धि) तथा वाणिज्य में 45.60% वृद्धि (87 विद्यार्थियों की वृद्धि)

कला और विज्ञान में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है, जबकि वाणिज्य में वृद्धि अपेक्षाकृत कम रही है। कुल मिलाकर, तीनों क्षेत्रों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है, जो शिक्षा में रुचि और विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव को दर्शाता है।

3. आदर्श विद्यालय योजना के क्रियान्वयन के पश्चात् विद्यार्थियों के विद्यालय छोड़ देने की दर (Drop Out Rate) में आया परिवर्तन।

सारणी संख्या:-1.4

		जुलाई 2014	जुलाई 2024	प्रतिशत में वृद्धि
ड्रॉप आउट	छात्र	54	6	-88.89
	छात्रा	128	31	-75.78
	योग	182	37	-79.67



आरेख संख्या : 1.3

**विश्लेषण एवं व्याख्या:-**

सारणी संख्या 1.4 एवं आरेख संख्या 1.3 से स्पष्ट है कि जुलाई 2014 से जुलाई 2024 तक ड्रॉपआउट दर में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है। जुलाई 2014 में जहां 54 छात्र और 128 छात्राएँ ड्रॉपआउट थीं, वहीं जुलाई 2024 में यह संख्या घटकर क्रमशः 6 और 31 हो गई। इस प्रकार, छात्रों का ड्रॉपआउट 88.89% और छात्राओं का 75.78% कम हुआ। कुल मिलाकर, 182 ड्रॉपआउट की संख्या 37 तक पहुँच गई, जो कि 79.67% की गिरावट को दर्शाता है। यह गिरावट शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और विभिन्न योजनाओं के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाती है, जिससे छात्रों और छात्राओं की ड्रॉपआउट दर में कमी आई है। यह एक सकारात्मक बदलाव है, जो भविष्य में शैक्षिक स्तर को सुधारने में सहायक हो सकता है।

4. आदर्श विद्यालय योजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रारंभिक शिक्षा के शैक्षिक-प्रशासनिक ढांचे (Administrative Structure for Education) में आया परिवर्तन।

**सारणी संख्या: 1.5**

स्तर	2014	2024
राज्य स्तर (सचिवालय स्तर - जयपुर)	शिक्षा सचिव (स्कूल शिक्षा)	शिक्षा सचिव (स्कूल शिक्षा)
निदेशालय स्तर -बीकानेर	निदेशक (प्रारम्भिक) निदेशक (माध्यमिक)	निदेशक (प्रारम्भिक) निदेशक (माध्यमिक)
मण्डल स्तर	उपनिदेशक (प्रारम्भिक) उपनिदेशक (माध्यमिक)	संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा
जिला	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक)	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (उपनिदेशक के समकक्ष)
	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)	जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (मुख्यालय)
	-	जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक (मुख्यालय)
	प्रधानाचार्य (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान) डाईट	प्रधानाचार्य (जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान) डाईट
ब्लॉक	ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (बी.ई.ई.ओ.) प्रधानाचार्य समकक्ष	मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (सी.बी.ई.ओ.) जिला शिक्षा अधिकारी (समकक्ष)
ग्राम पंचायत	-	पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पी.ई.ई.ओ.) आहरण-वितरण अधिकारी
विद्यालय	प्रधानाध्यापक (प्राथमिक विद्यालय) प्रधानाध्यापक (उच्च प्राथमिक विद्यालय) प्रधानाध्यापक (माध्यमिक विद्यालय) प्रधानाचार्य (उच्च माध्यमिक विद्यालय)	प्रधानाध्यापक (प्राथमिक विद्यालय) प्रधानाध्यापक (उच्च प्राथमिक विद्यालय) प्रधानाचार्य (उच्च माध्यमिक विद्यालय) उप-प्रधानाचार्य (उच्च माध्यमिक विद्यालय)

**व्याख्या एवं विश्लेषण:**

यह तालिका 2014 और 2024 के बीच शिक्षा विभाग में पदों की स्थिति और उनके बदलावों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। राज्य स्तर पर शिक्षा सचिव (स्कूल शिक्षा) का पद 2014 से लेकर 2024 तक समान बना हुआ है। निदेशालय स्तर पर भी प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के निदेशकों के पद में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। मण्डल स्तर पर 2014 में उपनिदेशक (प्रारंभिक) और उपनिदेशक (माध्यमिक) जैसे पद थे, जो 2024 में "संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा" के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। जिला स्तर पर, जहां 2014 में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) और जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के पद थे, 2024 में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) को "मुख्यालय" के रूप में विस्तारित किया गया है, जबकि जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) का पद बना हुआ है। ब्लॉक स्तर पर, 2014 में ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी और प्रधानाचार्य समकक्ष थे, जो अब 2024 में "मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी" के रूप में बदल गए हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर 2024 में नए पदों जैसे "पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी" (आहरण-वितरण अधिकारी) जोड़े गए हैं, जो 2014 में नहीं थे। विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के पदों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, हालांकि "उप-प्रधानाचार्य (उच्च माध्यमिक विद्यालय)" का नया पद जोड़ा गया है। यह तालिका शिक्षा विभाग में सुधार और संरचनात्मक बदलावों को दर्शाती है, जिनका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता और प्रबंधन को बेहतर बनाना है।

- आदर्श विद्यालय योजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं (Infrastructure Facilities) एवं भौतिक संसाधनों (Physical Resources) में आया परिवर्तन।

**भाग-अ****अवलोकन के आधार पर भौतिक स्थिति****सारणी संख्या 1.6****विद्यालय भवन**

क्र.स.	सुविधाएँ	आसीन्द ब्लॉक		बदनोर ब्लॉक		योग	
		हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
i	विद्यालय भवन	77.78	22.22	88.89	11.11	83.33	16.67
ii	पुस्तकालय	55.56	44.44	64.81	35.19	60.19	39.81
iii	प्रयोगशाला	83.33	16.67	77.78	22.22	80.56	19.44
iv	खेल सुविधाएँ	57.78	42.22	71.11	28.89	64.44	35.56
v	प्रशासनिक कार्यालय	62.22	37.78	57.78	42.22	60.00	40.00
vi	ऑडिटोरियम/बहु-उद्देशीय हॉल	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00
vii	सुरक्षा उपाय	88.27	13.53	94.93	6.87	93.20	10.40
viii	आई.सी.टी. संरचना	54.32	45.68	49.38	50.62	51.85	48.15

ix	शिक्षण अधिगम सामग्री	92.59	7.41	81.48	18.52	87.04	12.96
x	प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएँ	75.56	24.44	84.44	15.56	80.00	20.00
xi	दिव्यांग विद्यार्थियों हेतु सुविधाएँ	20.63	79.37	14.29	85.71	17.46	82.54
	योग	69.82	30.34	71.35	28.81	70.73	29.59



आरेख संख्या:1.4

**व्याख्या एवं विश्लेषण:**

सारणी संख्या 1.6 एवं आरेख संख्या 1.4 से स्पष्ट है कि कुछ सुविधाएँ, जैसे कि ऑडिटोरियम (100%), सुरक्षा उपाय (आसीन्द 88.27%, बदनोर 94.93%), और शिक्षण सामग्री (आसीन्द 92.59%, बदनोर 81.48%) दोनों ब्लॉकों में अच्छी तरह उपलब्ध हैं। वहीं, पुस्तकालय (आसीन्द 55.56%, बदनोर 64.81%) और खेल सुविधाएँ (आसीन्द 57.78%, बदनोर 71.11%) की उपलब्धता कम है। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सुविधाएँ (आसीन्द 20.63%, बदनोर 14.29%) भी बहुत कम हैं। प्रशासनिक कार्यालय (आसीन्द 62.22%, बदनोर 57.78%) और प्रयोगशाला (आसीन्द 83.33%, बदनोर 77.78%) की सुविधाएँ दोनों ब्लॉकों में उपलब्ध हैं, जबकि आई.सी.टी. संरचना (आसीन्द 54.32%, बदनोर 49.38%) में सुधार की आवश्यकता है। इन आंकड़ों से यह स्पष्ट है कि कुछ क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है ताकि सभी छात्रों के लिए समान और बेहतर सुविधाएँ सुनिश्चित की जा सकें।

**भाग-ब****शिक्षकों के अनुसार भौतिक संसाधनों की स्थिति**

सारणी संख्या:1.7

क्र.स.	कथन	आसींद			बदनोर			योग		
		हाँ	नहीं	अनिश्चित	हाँ	नहीं	अनिश्चित	हाँ	नहीं	अनिश्चित
1.	विद्यालय में पर्याप्त	88.89	11.11	0.00	88.89	11.11	0.00	88.89	11.11	0.00

	कक्षा-कक्ष है।									
2.	विद्यालय में पर्याप्त शिक्षण अधिगम सामग्री में है।	100.00	0.00	0.00	83.33	16.67	0.00	91.67	8.33	0.00
3.	विद्यालय में पीने के पानी सुविधा है।	100.00	0.00	0.00	94.44	0.00	5.56	97.22	0.00	2.78
4.	छात्र-छात्राओं हेतु पृथक पृथक शौचालय की व्यवस्था है।	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
5.	पुस्तकालय कक्ष उपलब्ध है।	94.44	5.56	0.00	94.44	5.56	0.00	94.44	5.56	0.00
6.	पुस्तकालय में पर्याप्त मात्रा में संदर्भ पुस्तकें उपलब्ध है।	61.11	38.89	0.00	55.56	38.89	5.56	58.33	38.89	2.78
7.	चारदीवारी युक्त खेल का मैदान है।	27.78	72.22	0.00	27.78	72.22	0.00	27.78	72.22	0.00
8.	पर्याप्त खेल सामग्री उपलब्ध है।	33.33	66.67	0.00	11.11	83.33	5.56	22.22	75.00	2.78
9.	अभिभावक-शिक्षक बैठक कक्ष उपलब्ध है।	50.00	50.00	0.00	27.78	72.22	0.00	38.89	61.11	0.00
10.	कंप्यूटर लैब उपलब्ध है।	100.00	0.00	0.00	88.89	11.11	0.00	94.44	5.56	0.00
11.	लैब में पर्याप्त कंप्यूटर उपलब्ध है।	66.67	33.33	0.00	83.33	16.67	0.00	75.00	25.00	0.00
	<b>योग</b>	<b>74.75</b>	<b>25.25</b>	<b>0.00</b>	<b>68.69</b>	<b>29.80</b>	<b>1.52</b>	<b>71.72</b>	<b>27.53</b>	<b>0.76</b>



आरेख संख्या: 1.5

**व्याख्या एवं विश्लेषण:**

सारणी संख्या 1.7 एवं आरेख संख्या 1.5 के अनुसार, विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की स्थिति मिश्रित है। कक्षा-कक्ष (88.89%) और पीने का पानी (100%) सहित शौचालय (100%) और कंप्यूटर लैब (100%) की स्थिति अधिकांश शिक्षकों के अनुसार अच्छी है। पुस्तकालय में संदर्भ पुस्तकों की कमी है, क्योंकि 38.89% शिक्षक इसे पर्याप्त नहीं मानते हैं। खेल का मैदान (72.22%) और खेल सामग्री (66.67%) की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है, जबकि अभिभावक-शिक्षक बैठक कक्ष (50%) की उपलब्धता में असमानता पाई गई है। इस प्रकार, कुछ भौतिक संसाधनों में सुधार की आवश्यकता है, जबकि अन्य सुविधाएं संतोषजनक हैं।

**भाग-स****विद्यार्थियों के अनुसार भौतिक मानव संसाधनों की स्थिति**

सारणी संख्या :1.8

क्र.स.	कथन	आसींद		बदनोर		योग		
		हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	योग
1.	आपके विद्यालय में छात्र तथा छात्राएँ दोनों एक ही शौचालय का उपयोग करते हैं।	4.44	95.56	0.00	100.00	2.22	97.78	100
2.	आप पुस्तकालय से नियमित रूप में पुस्तकें इश्यू करवाते हैं।	82.22	17.78	51.11	48.89	66.67	33.33	100
3.	आपको प्रत्येक विषय अलग-अलग शिक्षक पढ़ाते हैं।	97.78	2.22	97.78	2.22	97.78	2.22	100
4.	विद्यालय में आपके खेलने के लिए पर्याप्त खेल सामग्री उपलब्ध है।	73.33	26.67	44.44	55.56	58.89	41.11	100
5.	कंप्यूटर कक्षाओं का संचालन नियमित रूप से होता है।	40.00	60.00	28.89	71.11	34.44	65.56	100
6.	विद्यालय में सभी विद्यार्थियों के लिए स्वच्छ पेयजल व्यवस्था है?	97.78	2.22	100.00	0.00	98.89	1.11	100

7.	विद्यालय में सभी विद्यार्थियों हेतु शौचालय-मूत्रालय की व्यवस्था हैं?	97.78	2.22	100.00	0.00	98.89	1.11	100
8.	विद्यालय में विद्यार्थी नियमित रूप से पुस्तकालय सुविधा का उपयोग करते हैं ?	93.33	6.67	86.67	13.33	90.00	10.00	100
9.	विद्यालय में सभी विद्यार्थियों हेतु पाठ्यतर गतिविधियों का आयोजन करवाया जाता है?	88.89	11.11	80.00	20.00	84.44	15.56	100
	<b>योग</b>	<b>75.06</b>	<b>24.94</b>	<b>65.43</b>	<b>34.57</b>	<b>70.25</b>	<b>29.75</b>	<b>100</b>

### विश्लेषण एवं व्याख्या:

सारणी संख्या 1.8 से स्पष्ट है कि **95.56%** विद्यार्थियों ने शौचालय के लिए अलग-अलग व्यवस्था की बात की है, जबकि **82.22%** ने पुस्तकालय से नियमित पुस्तकें इश्यू करने की पुष्टि की। **97.78%** विद्यार्थियों ने बताया कि प्रत्येक विषय के लिए अलग शिक्षक हैं। **73.33%** विद्यार्थियों ने खेल सामग्री की उपलब्धता पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, लेकिन **60%** ने कम्प्यूटर कक्षाओं की नियमितता पर सवाल उठाया। **97.78%** विद्यार्थियों ने स्वच्छ पेयजल और शौचालय सुविधाओं की पुष्टि की। **93.33%** विद्यार्थियों ने पुस्तकालय का नियमित उपयोग किया, और **88.89%** ने पाठ्यतर गतिविधियों के आयोजन की पुष्टि की। कुल मिलाकर, अधिकतर सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है।

विद्यालय में संसाधनों की उपलब्धता:-

सारणी संख्या:1.9

क्र.स.	कथन	आसंद		बदनोर		योग		
		हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	योग
1.	पर्याप्त सुविधाजनक कक्षा-कक्ष	97.78	2.22	97.78	2.22	97.78	2.22	100
2.	शिक्षण अधिगम सामग्री में (चार्ट, ग्लोब, मानचित्र, मॉडल, ज्योमिट्री बॉक्स, समय रेखा, मौसम प्रमापी यंत्र इत्यादि।)	73.33	26.67	40.00	60.00	56.67	43.33	100
3.	छात्र-छात्राओं हेतु पृथक पृथक शौचालय की व्यवस्था	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100
4.	पोषाहार कक्ष	97.78	2.22	100.00	0.00	98.89	1.11	100
5.	पुस्तकालय कक्ष	95.56	4.44	95.56	4.44	95.56	4.44	100
6.	चारदीवारी युक्त खेल का मैदान	37.78	62.22	33.33	66.67	35.56	64.44	100
7.	खेल सामग्री	80.00	20.00	62.22	37.78	71.11	28.89	100
8.	अभिभावक - शिक्षक बैठक कक्ष	97.78	2.22	100.00	0.00	98.89	1.11	100

9.	कंप्यूटर लैब	82.22	17.78	66.67	33.33	74.44	25.56	100
10	पर्याप्त कंप्यूटर	37.78	62.22	40.00	60.00	38.89	61.11	100
11.	विद्यालय प्रबन्धन समिति	97.78	2.22	88.89	11.11	93.33	6.67	100
12.	छात्र संघ	97.78	2.22	77.78	22.22	87.78	12.22	100
13.	अंग्रेजी शिक्षक	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100
14.	हिन्दी शिक्षक	97.78	2.22	95.56	4.44	96.67	3.33	100
15.	तृतीय भाषा शिक्षक	73.33	26.67	68.89	31.11	71.11	28.89	100
16.	विज्ञान शिक्षक	20.00	80.00	28.89	71.11	24.44	75.56	100
17.	सामाजिक विज्ञान शिक्षक	95.56	4.44	77.78	22.22	86.67	13.33	100
18.	गणित शिक्षक	20.00	80.00	24.44	75.56	22.22	77.78	100
19.	स्वास्थ्य शिक्षा अध्यापक	100.00	0.00	93.33	6.67	96.67	3.33	100
20.	पुस्तकालय अध्यक्ष	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	100
	योग	80.11	19.89	74.56	25.44	77.33	22.67	100

### व्याख्या एवं विश्लेषण:

सारणी संख्या 1.9 से स्पष्ट है कि इस तालिका में अधिकांश स्कूल सुविधाएं जैसे कक्षा, पुस्तकालय, शौचालय और शिक्षक उपलब्धता अच्छी हैं, जिनमें "हाँ" का प्रतिशत 95% से 100% तक है। हालांकि, खेल का मैदान, कंप्यूटर लैब और खेल सामग्री में सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में "नहीं" का प्रतिशत अधिक है। शिक्षक उपलब्धता के मामले में विज्ञान और गणित के लिए शिक्षक की कमी दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर, स्कूल की सुविधाओं में संतोषजनक स्थिति है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है।

### भाग-द

#### प्रधानाचार्यों के अनुसार भौतिक स्थिति

- आदर्श विद्यालय योजना के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक (Teaching And Non Teaching) श्रेणी के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों आया परिवर्तन।

#### पदस्थापन स्थिति सारणी संख्या:1.10

शैक्षणिक	कार्यरत		रिक्त		स्वीकृत	
	पदों की संख्या	%	पदों की संख्या	%	पदों की संख्या	%
प्रधानाचार्य	6	33.33	12	66.67	18	100
उप-प्रधानाचार्य	5	27.77	13	72.23	18	100
प्राध्यापक	85	71.43	34	28.57	119	100
वरिष्ठ अध्यापक	53	62.35	32	37.65	85	100

अध्यापक (L 1)	56	88.89	7	11.11	63	100
अध्यापक (L 2)	55	84.62	10	15.38	65	100
कंप्यूटर अनुदेशक	11	64.71	6	35.29	17	100
शारीरिक शिक्षक	16	88.89	2	11.11	18	100
योग शैक्षणिक	282	69.98	121	30.02	403	100

गैर-शैक्षणिक	कार्यरत		रिक्त		स्वीकृत	
	पदों की संख्या	%	पदों की संख्या	%	पदों की संख्या	%
कनिष्क सहायक	11	61.11	7	38.89	18	100
वरिष्ठ सहायक	13	72.22	5	27.78	18	100
प्रयोगशाला सहायक	8	57.14	6	42.86	14	100
पुस्तकालयाध्यक्ष	5	41.67	7	58.33	12	100
सहायक कर्मचारी	10	20.83	38	79.17	48	100
योग अशैक्षणिक	47	42.73	63	57.27	110	100

शैक्षणिक अशैक्षणिक	एवं	कार्यरत		रिक्त		स्वीकृत	
		पदों की संख्या	%	पदों की संख्या	%	पदों की संख्या	%
योग		329	64.13	184	35.87	513	100

### व्याख्या एवं विश्लेषण:

सारणी संख्या 1.10 से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में शैक्षणिक और अशैक्षणिक पदों की स्थिति पर आधारित दत्तों के अनुसार, शैक्षणिक श्रेणी में कुल 64.13% पद कार्यरत हैं, जबकि 35.87% पद रिक्त हैं। प्रधानाचार्य (33.33%) और उप-प्रधानाचार्य (27.77%) पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कम है, जबकि रिक्त पदों की संख्या अधिक है। प्राध्यापक (71.43%) और वरिष्ठ अध्यापक (62.35%) पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का प्रतिशत बेहतर है, हालांकि रिक्त पद भी मौजूद हैं। अध्यापक (L1) और अध्यापक (L2) के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का प्रतिशत 88.89% और 84.62% है, जो यह दर्शाता है कि इन पदों पर नियुक्ति बेहतर है। कंप्यूटर अनुदेशक (64.71%) और शारीरिक शिक्षक (88.89%) के पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति भी सकारात्मक है, हालांकि कुछ रिक्तियां हैं।

अशैक्षणिक श्रेणी में कुल 42.73% पद कार्यरत हैं, जबकि 57.27% पद रिक्त हैं। कनिष्क सहायक (61.11%) और वरिष्ठ सहायक (72.22%) पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है, जबकि प्रयोगशाला सहायक (57.14%) और पुस्तकालयाध्यक्ष (41.67%) पदों पर रिक्तियां अधिक हैं। सहायक कर्मचारी पदों पर कार्यरत कर्मचारियों का प्रतिशत केवल 20.83% है, जबकि रिक्त पदों की संख्या 79.17% है, जो अशैक्षणिक श्रेणी में गंभीर कमी को दर्शाता है।

कुल मिलाकर, विद्यालयों में शैक्षणिक कर्मचारियों की स्थिति बेहतर है, लेकिन अशैक्षणिक कर्मचारियों की संख्या में पर्याप्त कमी है। शैक्षणिक पदों में सुधार की आवश्यकता है, विशेष रूप से प्रधानाचार्य और उप-प्रधानाचार्य के पदों पर, जबकि अशैक्षणिक श्रेणी में कर्मचारियों की नियुक्ति पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

### निष्कर्ष (Comprehensive Conclusion):

आदर्श विद्यालय योजना राजस्थान राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है, जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को सुधारना और विद्यार्थियों की शिक्षा में भागीदारी को बढ़ावा देना था। इस योजना ने शिक्षण प्रक्रिया, शैक्षिक अवसंरचना, और प्रशासनिक ढांचे में सकारात्मक बदलाव लाए हैं, जो राज्य के दूर-दराज के क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बेहतर बनाने के दिशा में महत्वपूर्ण हैं।

1. शैक्षिक सुधार और छात्र संख्या में वृद्धि: योजना के तहत कक्षा 11 और 12 में विद्यार्थियों के नामांकन में 57.41% की वृद्धि देखी गई है, जो यह दर्शाता है कि शिक्षा के प्रति ग्रामीण विद्यार्थियों का रुझान बढ़ा है। विशेष रूप से, विज्ञान, कला, और वाणिज्य जैसे विभिन्न पाठ्यक्रमों में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव का संकेत है। इससे यह साफ है कि आदर्श विद्यालय योजना ने शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों की जागरूकता और अभिरुचि में सुधार किया है।
2. ड्रॉपआउट दर में कमी: इस योजना के प्रभाव से ड्रॉपआउट दर में 79.67% की गिरावट आई है, जिससे यह साबित होता है कि योजना ने छात्रों को शिक्षा में बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। यह गिरावट यह दर्शाती है कि छात्र अब स्कूल छोड़ने के बजाय शिक्षा की यात्रा को जारी रखने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। इस सुधार के पीछे मूल्यांकन, शिक्षक समर्थन, और विद्यालय के माहौल में सुधार का योगदान है।
3. भौतिक अवसंरचना और शैक्षिक संसाधनों में सुधार: योजना ने विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की स्थिति को बेहतर किया है। विद्यालयों में प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, और खेल सुविधाओं में वृद्धि की गई है, जो विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक अनुभव प्रदान करती हैं। हालांकि, कुछ क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है, जैसे दिव्यांग छात्रों के लिए सुविधाएं और पुस्तकालयों में संदर्भ सामग्री। इन सुविधाओं के बेहतर वितरण से शिक्षा का वातावरण और अधिक समावेशी और प्रभावी बन सकता है।
4. शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन में सुधार: शैक्षिक प्रशासन में सुधार के प्रयास किए गए हैं, जैसे कि नए पदों का सृजन और प्रशासनिक संरचनाओं में सुधार। इससे शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर समन्वय और प्रबंधन हुआ है। नए प्रशासनिक उपायों के साथ-साथ स्मार्ट स्कूल प्रणाली और डिजिटल शिक्षा सामग्री का उपयोग बढ़ा है, जिससे शैक्षिक प्रक्रिया को गति मिली है और विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त हो रही है।
5. राज्य सरकार की भूमिका और नीति: राज्य सरकार की नीतियां और वित्तीय समर्थन भी इस योजना की सफलता में अहम रहे हैं। सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए विभिन्न निवेशों और योजनाओं ने स्कूलों

की स्थिति में सुधार किया है और विद्यार्थियों के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा, सरकारी योजनाओं के प्रचार-प्रसार से भी छात्रों और अभिभावकों को शिक्षा की महत्वता और उपलब्ध अवसरों के बारे में जानकारी मिली है।

### संदर्भ सूची:

1. द्वौडियाल, एस.; फाटक, अरविन्द (2005). *शैक्षिक अनुसंधान का विधिशास्त्र*. जयपुर: राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी।
2. देवी एस, महेश ई. (2005). *ओडिशा में अनुसूचित जनजाति की शिक्षा का विकास: "द पेसा" अधिनियम की भूमिका*, भुवनेश्वर : मोनोग्राफ 6-17.
3. देसाई एस. कुलकर्णी वी (2008). *भारत में शैक्षणिक असमानताओं को बदलना सकारात्मक कार्रवाई संदर्भ में, डेमो अंजीर*, 45 (2) 245-270
4. गैरट, हेनरी ई. (1990). *शिक्षा और मनोविज्ञान में सांख्यिकी*. नई दिल्ली: कल्याणी पब्लिशर्स।
5. कपिल, एच.के. (1981). *अनुसंधान विधियाँ*. आगरा: हर प्रसाद भार्गव पुस्तक प्रकाशन।
6. भरतीया, विपुल कुमार (2004) "गुजरात एवं राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में सर्वशिक्षा अभियान के प्रति शिक्षकों एवं अभिभावकों के अभिमत का अध्ययन" लघुशोध प्रबंध (मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर)
7. अय्यर, त्रिद्विमेश (2004) "प्राथमिक शिक्षा में सरकारी एवं गैर-सरकारी प्रयासों का अध्ययन", पीएच.डी.।
8. कुमार संजय (2018) "राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एक समीक्षात्मक अध्ययन (झुंझुनू जिले के सन्दर्भ में)" राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर
9. पाल मुनू (2018) "शिक्षा के सार्वभौमीकरण की योजना - का समीक्षात्मक अध्ययन"
10. यूनिसेफ इंडिया (2013-2014) "रैपिड सर्वे ऑफ चिल्ड्रेन"
11. राजगोपाल शोभिता (2018) ने "शिक्षा में अभिनव कार्यक्रमों से प्राप्त सबक: लोक जुम्बिश"
12. राष्ट्रीय शिक्षा नीति दस्तावेज 2020
13. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार (2023-24) "यूडीआईएसई प्लस रिपोर्ट"
14. दृष्टि आईएस (2021) "बालिकाओं को स्कूल में बनाए रखना।"
15. [www.dissertationindia.com](http://www.dissertationindia.com)
16. [www.educationforallindia.com](http://www.educationforallindia.com)
17. [www.ncert.nic.in](http://www.ncert.nic.in)
18. [www.ncte.in.org/pub/rimse/spkl.hmt](http://www.ncte.in.org/pub/rimse/spkl.hmt).
19. [www.teachersmind.com/education.hmt](http://www.teachersmind.com/education.hmt).
20. [www.thesisabstract.com](http://www.thesisabstract.com)
21. [www.education.nic.in](http://www.education.nic.in)